रफ़ीक

बनाम

यू. पी. राज्य

14 अगस्त, 1980

[वी.आर. कृष्णा अय्यर और ओ.चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.जे.]

भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 136 - तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष-विचारण न्यायालय द्वारा बलात्कार के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील - सर्वोच्च न्यायालय कब हस्तक्षेप करेगा।

भारतीय दंड संहिता 1860, धारा 376 - साक्ष्य और प्रमाण – अभियोक्त्री पर चोटों की अनुपस्थिति – क्या अभियोजन के लिए घातक है –अभियोक्त्री की साक्ष्य - यदि आवश्यक हो तो पुष्टि करें।

याचिकाकर्ता को एक ग्राम कल्याण संगठन में एक बालिका विद्यालय में सो रही अधेड़ उम्र की बाल सेविका से बलात्कार करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। विचारण न्यायालय ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से प्रताप मिश्रा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, एएलआर 1977 एससी 1307 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया

था कि पीड़ित के शरीर पर चोटों का अभाव उसके लिए घातक था। बलात्कार के मामलों में अभियोजन और पुष्ट साक्ष्य न्यायिक विश्वशनीयता का एक अनिवार्य घटक थे। यह भी कहा गया कि 7 साल की सज़ा बहुत कठोर थी।

याचिका को खारिज करते हुए-

अभिनिर्धारित किया 1. दोष या सजा की मात्रा पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। [405 जी]

2. इस न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष आमतौर पर निवारक पवित्रता और अस्थायी अंतिमता प्राप्त कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष क्षेत्राधिकार, जो मुख्य रूप से प्रकट अन्याय या महान क्षण के कानून की त्रुटियों को ठीक करने के लिए है, को तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। %[403 एचह]

3. (i) तथ्य और परिस्थितियाँ अक्सर मामले-दर-मामले भिन्न होती हैं, अपराध की स्थिति और असंख्य मानसिक कारक, सामाजिक स्थितियाँ और लोगों की जीवन शैली में उतार-चढ़ाव हो सकता है, और इसलिए, एक तथ्य स्थिति में प्रासंगिक विवेक के नियम दूसरे में अयोग्य हो सकते हैं। यह तर्क कि किसी अपराध और आपराधिक परिवेश की विशिष्ट परिस्थितियों की परवाह किए बिना, संभावित तर्क के कुछ पहलू जो एक रिपोर्ट किए गए निर्णय में एक पीठ को अपील करते हैं, उन्हें यांत्रिक रूप

से अन्य मामलों में बढ़ाया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [404 डी]

(ii) प्रताप मिश्रा के मामले में किसी भी बिंदु पर कानून का कोई कठोर सिद्धांत नहीं दिया गया है। [404 सी]

4. अभियोक्त्री की गवाही पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में पुष्टि करना कानून का मामला नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। [404 ई]

तत्काल मामले में अभियोक्त्री की साक्ष्य को दो न्यायालयों द्वारा स्वीकृति दी गई है। एक संवेदनशील न्यायाधीश जो परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य को उसकी समग्रता में देखता है, शायद ही किसी बलात्कार पीड़िता की गवाही को अस्वीकार करता है जब तक कि इसकी सत्यता के खिलाफ बहुत मजबूत परिस्थितियां न हों। इस मामले में कुछ भी नहीं है। इसलिए, निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि निश्चित रूप से एक विषय होना चाहिए। [404 एच, 405 बी}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अवकाश याचिका (आपराधिक) संख्या 950/1980

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2305/74 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21-9-1979 से उत्पन्न।

यू. एस. प्रसाद, याचिकाकर्ता की और से ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

कृष्णा अय्यर, न्यायाधिपति.- यह विशेष अनुमति याचिका बलात्कार के अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा से संबंधित है। इस तरह के अपराधों की वृद्धि इस हद तक पहुंच गई है कि यह देश के आध्यात्मिक नेतृत्व और सेल्युलाइड सेंसरशिप के दिखावे को उजागर करता है,, हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और मानवीय दावों को शर्मसार करती है और मानवाधिकारों पर एक अश्लील मर्दाना आक्रोश को उजागर करती है जिसमें महिला की व्यक्तिगत गरिमा एक पवित्र घटक है। हम विशेष छुट्टी से इनकार करते हैं और ऐसा करने के लिए संक्षेप में कुछ कारण बताते हैं।

द्रौपदी, एक ग्राम कल्याण संगठन में एक मध्यम आयु वर्ग की बाल सेविका, एक लड़कियों के स्कूल में सो रही थी जहाँ उसके साथ याचिकाकर्ता रफीक और तीन अन्य लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। यह अपराध 22/23 अगस्त, 1971 को लगभग 2.30 बजे सुबह हुआ और अगली सुबह पीड़िता ने घटना के बारे में गाँव की मुखिया सेविका को बताया। 23 अगस्त 1971 को दोपहर के समय पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद हुई जांच में आरोप-पत्र, मुकदमा और, अंततः, पीड़ित की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हुई। हालाँकि कुछ गवाहों ने, कहानी के अनुसार, अपनी वफादारी बदल दी और अभियोजन

पक्ष के मामले को धोखा दिया, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकाला, जिससे अन्य तीन को अस्पष्ट रूप से संदेह का लाभ मिला। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा न्यायोचित रूप से दी गई। उच्च न्यायालय में की गई अपील असफल साबित हुई लेकिन, निडर होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी है।

इस न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष आम तौर पर एक निवारक पवित्रता और अस्थायी अंतिमता प्राप्त करते हैं और हम शायद ही कभी संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हैं, जिसका मुख्य रूप से प्रकट अपराध या महान क्षण के कानून की त्रुटियों को ठीक करना है। इन ठोस सिद्धांतों के अनुसार अवकाश के लिए वर्तमान याचिका में एक क्षण का भी मौका नहीं है।

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजक की साक्ष्य की पुष्टि का अभाव था कि महिला के शरीर पर चोटों का अभाव था और इसलिए परीक्षण किया गया केस-कानून की कसौटी पर दोषसिद्धि असमपोश्नीय थी। इनमें से किसी भी तर्क में कोई बल नहीं है और सामान्य तौर पर, हमें बोलने का आदेश देने से भी बचना चाहिए था, लेकिन अधिवक्ता ने प्रताप मिश्रा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य में इस न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और आग्रह किया कि व्यक्ति पर कोई चोट नहीं होनी चाहिए। पीड़िता की

स्थिति अभियोजन पक्ष के लिए घातक थी और बलात्कार के मामलों में पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक विश्वशनीयता का एक अनिवार्य घटक था।

हम सहमत नहीं हैं। एक बात के लिए, प्रताप मिश्रा के मामले (सुप्रा) ने किसी भी बिंदु पर कानून का कोई लचीला सिद्धांत नहीं रखा। तथ्य और परिस्थितियाँ अक्सर मामले-दर-मामले भिन्न होती हैं। अपराध की स्थिति और असंख्य मानसिक कारक, सामाजिक परिस्थितियाँ और लोगों की जीवन-शैली में उतार-चढ़ाव हो सकता है, और इसलिए, एक तथ्य-स्थिति में प्रासंगिक विवेक के नियम दूसरे में अयोग्य हो सकते हैं। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि किसी अपराध और आपराधिक परिवेश की विशिष्ट परिस्थितियों की परवाह किए बिना, संभावित तर्क के कुछ पहलू जो एक रिपोर्ट किए गए निर्णय में एक पीठ को अपील करते हैं, उन्हें यांत्रिक रूप से अन्य मामलों में बढ़ाया जाना चाहिए। अभियोक्त्री की गवाही पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में संपुष्टि कानून का मामला नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। दरअसल, जगह-जगह से, उम्र से उम्र तक, अलग-अलग जीवन-शैलियों और व्यवहारिक जटिलताओं से, मौखिक और परिस्थितिजन्य तथ्यों के दिए गए सेट से निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता हो सकती है, न कि मृत एकरूपता के साथ, बल्कि यथार्थवादी विविधता के साथ, अन्यथा आकार में कठोरता नहीं आएगी। इस क्षेत्र में कानून का शासन एक नए प्रकार के पूर्ववर्ती अत्याचार के माध्यम से लागू किया जाएगा। यही अवलोकन

आक्रामक या आक्रामक व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के संबंध में भी लागू होता है।

इंडो-एंग्लियन न्यायशास्त्र में आपराधिक कानून की कई "पवित्र गायेंÑÑ हैं जो अंधविश्वासी अस्तित्व में हैं और उनकी फिर से जांच की जानी चाहिए। जब बलात्कारी अपनी अनैतिक गतिविधियों में आनंद ले रहे हैं और मानव जाति का आधा हिस्सा-नारी जाति अपनी अभागी स्थिति के खिलाफ विरोध कर रही है, जब कोई भी सम्मानित महिला किसी अन्य पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाएगी क्योंकि वह अपनी सबसे प्रिय चीज़ का बलिदान करती है, हम एक जीवाश्म सूत्र पर टिके नहीं रह सकते हैं और जोर नहीं दे सकते हैं पुष्टिकारक गवाही पर, भले ही समग्र रूप से लिया जाए, पीड़ित द्वारा बोला गया मामला संभावित रूप से न्यायिक दिमाग पर प्रहार करता है। इस मामले में, गवाही को दो न्यायालयों से स्वीकृति का आदेश मिला है। जब किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो वह केवल शारीरिक चोट नहीं होती, बल्कि "कुछ मृत्युहीन शर्मिंदगी की गहरी भावन" होती है।

"एक बलात्कार! एक बलात्कार! .....

हाँ, आपको न्याय मिला है;

उसे अपनी खुशी करने के लिए मजबूर किया।

शायद ही कोई संवेदनशील न्यायाधीश होगा जो परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य को उसकी समग्रता में देखता है और बलात्कार पीड़िता की गवाही को तब तक खारिज कर देता है जब तक कि इसके विपरीत बहुत मजबूत परिस्थितियां न हों, यह सत्यता है। हम उसके मामले में किसी को नहीं देखते हैं, और इसलिए नीचे के न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि निश्चित रूप से होनी चाहिए। मानवाधिकारों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया को कानूनी कट्टरता से कुंद नहीं किया जा सकता।

हमारे सामने मामला 1971 में घटित हुआ और 1980 में ख़त्म होने वाला है। अफ़सोस की बात है! अब जब बलात्कार के मामलों की हिंसक आवृत्ति पर काफी सार्वजनिक और संसदीय ध्यान है, तो समय आ गया है कि न्यायालय राष्ट्र को याद दिलाए कि त्वरित जांच, त्वरित अभियोजन और तत्काल अंतिम निर्णय से निवारण अधिक प्रभावी ढंग से आता है, जिसमें साक्ष्य के विशेष नियम और परीक्षण के लिए विशेष एजेंसियां शामिल हैं। दंडात्मक गंभीरता की यांत्रिक वृद्धि, बिना किसी हिचकिचाहट के, महिला पीड़ितों के लिए खराब लाभांश उत्पन्न कर सकती है। डॉ.जॉनसन के समय में इंग्लैंड में जेबकतरों के लिए सार्वजनिक फांसी का चलन था, लेकिन जैसा कि डॉ.जॉनसन ने जेबकतरों पर व्यंग्यपूर्वक उल्लेख किया था, किसी जेबकतरे को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाए जाने को देखने के लिए एकत्र हुई भीड़ के बीच अपना व्यापार करने में व्यस्त थे। डॉ.जॉनसन की बुद्धि हमारी बुद्धि है। अपराध-मुक्त समाज की रणनीति

सजा में कठोर कठोरता नहीं, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता, प्रक्रियात्मकता, गतिहीनता और संबंधित समुदाय के बीच त्वरित प्रचार है। "अराजकता को दंड संहिता में कम कठोर प्रावधानों के बजाय एक पिछलग्गू, दीर्घकालिक, लापरवाही और कानूनी मुकदमेबाजी सिंड्रोम द्वारा बढ़ावा दिया जाता हैÑÑ। ध्यान बुराई पर होना चाहिए, न कि उसके पड़ोस पर।

अधिवक्ता ने कहा कि 7 साल की सज़ा बहुत गंभीर है। नहीं, क्योंकि, जैसा कि हमने पहले कहा है, एक महिला के लिए बलात्कार मृत्युहीन शर्म की बात है और इसे मानवीय गरिमा के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध के रूप में निपटाया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में दोषी होने या सज़ा की मात्रा के संबंध में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हम विशेष अवकाश से इनकार करते हैं।

एनवीके.

याचिका खारिज की गई।

(1) ए आई आर 1977 एस सी 1307

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****